रिटायर्ड कर्मचारी दंपति की गोली मारकर हत्या

तलाश में जुटी पुलिस

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 27 जून. ऐशबाग थाना इलाके में करोड़ों की संपत्ति के मालिक रहे एक बुजुर्ग दंपति के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई. शनिवार को शव का पुलिस ने पीएम कराया. अज्ञात हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है. सुदामा नगर में रहने वाले बुजुर्ग दंपति का खून से लथपथ शव शुक्रवार को देर रात उनके ही मकान के अंदर से पुलिस ने बरामद किया.

घर के अंदर से बाहर तक दुर्गंध आने के बाद पुलिस ने दरवाजा खोलकर शव को बाहर निकाला. पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि पति और पत्नी के नाम करीब दो-दो करोड़ रुपए की संपत्ति थी. संपत्ति विवाद समेत सभी पहलुओं की भी पुलिस जांच की जा रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है.

जानकारी के मुताबिक दंपति 70 वर्षीय हेमंत बारीक और पत्नी वर्षीय शकुंतला बारीक (70) का शव उनके ही घर के अंदर पाया गया. हेमंत का शव फर्श और शकुंतला का शव सोफे पर पड़ा मिला. दोनों के शरीर में दो -दो गोली लगी हैं. एक गोली शकुंतला के पेट में धंसी मिली. कयास लगाया जा रहा है कि अज्ञात हमलावर ने सटीक निशाना लगाते हुए दोनों से कुछ दूरी बनाते हुए गोली चलाई.



ऐशबाग थाना प्रभारी संदीप पवार ने नवभारत को बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है. इस दौरान पुष्टि हुई कि दोनों को दो दो गोलियां लगी हैं. उन्होंने बताया कि जिस कक्ष में यह घटना हुई, उसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं, लटका हुआ मिला है. पुलिस ने अंदर जाकर शवों को कब्जे में लिया. घटनास्थल सील कर दिया गया है. दोनों की हत्या की आशंका है और विभिन्न पहुलओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

> दोनों ने रिटायर्ड कर्मचारी थे. हेमंत रेलवे विभाग में और शकुंतला कस्तूरबा अस्पताल नर्स के तौर पर पहले काम करती थी. उनकी कोई संतान नहीं थी. हेमंत ने अपने घर में ही किराएदार भी रखे थे. दोनों बुजुर्ग करीब दो दिन से घर से बाहर नहीं निकले थे. इसकी भी जानकारी पड़ोसियों और किराएदारों के माध्यम से पुलिस को हुई है. हत्या के इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. हेमंत के घर का दरवाजा अंदर से बंद होना, दंपती के सिर पर गोली लगना और अज्ञात हमलवार के गोली चलाने पर फायरिंग की आवाज लोगों तक नहीं आना, जैसे सवालों के जवाब पुलिस खंगाल रही है. घटना स्थल को पुलिस ने सील कर दिया है. दंपती के फोन को जब्त कर पुलिस कॉल डिटेल्स भी निकाल रही है. पुलिस ने हेमंत के किराएदारों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी है. हेमंत की भाभी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को आखिरी बार उनकी बातचीत दोनों के साथ हुई थी.

बीडीए की योजनाओं को दें गति, बैठक में दिए निर्देश

निज संवाददाता

भोपाल, 27 जून. संभाग आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने भोपाल विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की, जिसमें प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया.

बैठक में नवीन टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस), पुनर्विकास कार्यों, बीएमआर तथा एजु सिटी इकाई से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के दौरान सभी परियोजनाओं के प्रभावी संचालन और समय पर पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कार्यों में



किसी प्रकार की लापरवाही न हो और योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए. साथ ही परियोजनाओं की गुणवत्ता बनाए रखने और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देने की बात कही गई.

बच्चों को आज से पिलाई जाएगी पोलियो दवा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 जून. राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून से तीन दिन तक राजधानी सहित प्रदेशभर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी.

बता दें इस विशेष अभियान के तहत भोपाल जिले के करीब 3 लाख 32 हजार बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

जिसके लिये स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. वहीं बच्चों को आसानी से दवा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल जिले में 2710 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं. बता दें ये सभी बूथ आंगनवाड़ी केंद्रों, चिन्हित सरकारी और निजी अस्पतालों में बनाए गए हैं. इसके अतिरिक्त लोगों की सुविधा के लिए प्रमुख शॉपिंग मॉल्स और स्थानीय बाजारों में भी विशेष टीमें तैनात की गई हैं. यात्रा कर रहे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिले के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर विशेष नजर रखी जा रही है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों जैसे प्रमुख स्थानों पर ट्रांजिट बूथ बनाए गए हैं. जिससे जिले से बाहर जाने वाले या बाहर से भोपाल आने वाले किसी भी बच्चे को मौके पर ही पोलियो की खुराक दी जा सके.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि भले ही भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं. इस खतरे को देखते हुए 5 साल तक के सभी बच्चों को यह दवा पिलाना बेहद जरूरी है.

हाई रिस्क क्षेत्रों के लिए मोबाइल टीमें मुस्तैद

सड़क किनारे रहने वाली घुमक्कड़ आबादी, ईंट भट्ठों, स्टोन क्रेशरों और निर्माण स्थलों जैसे हाई रिस्क क्षेत्रों पर रहने वाले बच्चों तक पहुंचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल टीमें तैनात की हैं. ये टीमें इन क्षेत्रों में घूम-घूम कर बच्चों को तलाशेंगी और उन्हें दवा पिलाएंगी.

अस्पताल के बाथरूम में लटका मिला मरीज का शव

भोपाल. कजलीखेड़ा इलाके में एक अस्पताल में भर्ती मरीज ने बाथरूम के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक 48 वर्षीय दीपक शुक्ला किसानी का काम करते थे. दीपक मूलत: सागर जिले के रहवासी थे. पिछले कई महीनों से वे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान चल रहे थे. परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें कजलीखेड़ा स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया था. शुक्रवार को देररात दीपक अस्पताल के बाथरूम के अंदर गए और बहुत देर तक वापस नहीं आए. परिजनों और स्टाफ ने जब अंदर जा कर देखा तो वे फंदे पर लटके थे.

अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने सेल का गठन

सख्ती

- कॉलोनाइजर अब नहीं कर सकेंगे ठगी
- कॉलोनियों की निगरानी करेगा कॉलोनी सेल

भोपाल, 27 जून. एक ओर जिला प्रशासन शहर में डेवलप हो रही अवैध कॉलोनियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है, दूसरी ओर अब कॉलोनाइजर और डेवलपर आम लोगों के साथ ठगी न कर सकें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भोपाल में कॉलोनी सेल का गठन कर दिया गया है.

इसकी कमान एडीएम सुमित पांडेय को सौंपी गई हैं इस कॉलोनी सेल का काम शहर की सभी कॉलोनियों के डेवलपमेंट की निगरानी करना है. साथ कॉलोनाइजर्स को जारी होने वाले लाइसेंस भी इसी सेल के माध्यम से बनाए जाएंगे. इसके अलावा शहर में बनने वाली आवासीय कॉलोनियों को वैध या अवैध घोषित करना और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं का प्रबंधन करना भी कॉलोनी सेल के अंतर्गत ही आएगा. ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों और डेवलपर के बीच विकास कार्यों मुख्यत: पेयजल सप्लाई को लेकर होने वाले वाद विवाद इसी कॉलोनी सेल के जरिए निपटाएं जाएंगे.

बता दें कि वर्तमान में शहर के बाहरी इलाकों में कथित कॉलोनाइजर और डेवलपर कृषि भूमि का डायवर्जन किए बगैर फार्म हाउस के नाम पर 5 हजार वर्गफीट के प्लॉट बेचते हैं. इन प्लॉट को बेचते समय न तो टीएंडसीपी से और न ही रेरा से अनुमति ली जाती है. जिसके कारण भविष्य में लोगों को इन कॉलोनियों में पानी, सडक़, पार्क, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज नेटवर्क की सुविधा नहीं मिलती है. जिसके कारण प्लॉट खरीदने के बाद उपभोक्ता खुद को ठगा हुआ पाता है. कॉलोनाइजर प्लॉट, मकान बेचने के बाद गायब हो जाते हैं, जबकि लोग कलेक्ट्रेट और नगर निगम के चक्कर काटकर परेशान होते रहते हैं. कॉलोनी सेल से जहां कॉलोनाइजर व कॉलोनी को अनुमति तो मिलेगी ही, प्रॉपर्टी के खरीदारों के लिए भी यह उपयोगी विभाग साबित होगा.

कार्रवाई की जवाबदारी भी इसी सेल की होगी

शहर में अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने के लिए और कॉलोनाइजर की जवाबदारी तय करने के लिए कॉलोनी सेल का गठन किया गया है. इस सेल के गठन के बाद कॉलोनाइजर और कॉलोनी विकास की विभिन्न अनुमतियां यहीं से मिलेंगी और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जवाबदारी भी इसी सेल की होगी.
-प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर भोपाल



'क्लैट ऑन व्हील्स' में छात्रों ने दिखाया जोश

भोपाल, 27. भोपाल मेट्रो शनिवार को एक अनोखी पहल के तहत ज्ञान की पाठशाला बन गई. मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) की 'सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स' पॉलिसी के अंतर्गत 'क्लैट ऑन व्हील्स' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

यह कार्यक्रम सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से एम्स मेट्रो स्टेशन के बीच चलती मेट्रो में आयोजित हुआ.करीब दो घंटे तक चले इस आयोजन के लिए मेट्रो के दो कोच आरक्षित किए गए थे, जिनमें लगभग 100 छात्रों ने सहभागिता की. कार्यक्रम के दौरान सामान्य ज्ञान आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसने विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को परखा.इसके साथ ही करियर मार्गदर्शन सत्र में विशेषज्ञों ने छात्रों को लक्ष्य निर्धारण, व्यक्तित्व विकास और भविष्य की योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी.विद्यार्थियों ने खुलकर प्रश्न पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया.चलती मेट्रो में इस तरह का आयोजन छात्रों के लिए नया और रोमांचक अनुभव रहा.क्विज, संवाद और मार्गदर्शन के इस संयोजन ने सीखने को रोचक बना दिया.

आउटसोर्स कर्मियों का 75-75 हजार का एरियर बकाया

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 जून. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था संभालने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार के दावों के उलट भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा 29 मई और फिर 15 जून को कड़े निर्देश जारी करने के बाद भी जिलों में अधिकारियों ने कर्मचारियों के एरियर भुगतान में कोई रुचि नहीं दिखाई.

अनुमान के मुताबिक, दो साल से रुके हुए इस भुगतान के कारण प्रति कर्मचारी करीब 70 से 75 हजार रुपए का एरियर बकाया हो चुका है. वहीं अस्थायी और ठेका आउटसोर्स श्रमिक कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा का आरोप है कि अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते जानबूझकर कर्मचारियों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं अब विभागीय अनदेखी के खिलाफ अब प्रदेश के कई जिलों में कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. संगठन के अनुसार न्यूनतम वेतन और 26 महीने के बकाया एरियर की मांग को लेकर प्रदेश के 30 हजार स्वास्थ्य आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थाई कर्मचारी मोर्चा की भोपाल में एक अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें आंदोलन की अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी. कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही एरियर खातों में नहीं भेजा गया तो वे भोपाल पहुंचकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे.

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

भोपाल. कोलार थाना क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. मामले का खुलासा तब हुआ, जब छात्रा गर्भवती हो गई और परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग एक निजी स्कूल में पढ़ाई करती है. उसके माता-पिता किराए के घर में बच्चों के साथ रहते हैं. उनके ही पड़ोस में एक युवक रहता है और एक कैफे पर काम करता है. बीते 28 जनवरी को आरोपी छात्रा को घुमाने के बहाने से लेकर गया था. आरोपी ने मौका पाकर छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद उसने छात्रा को डरा धमका कर उसका लगातार दुष्कर्म करता रहा. दो दिन पहले छात्रा ने पेट दर्द की समस्या अपने परिजनों को बताई. परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डाक्टरों ने छात्रा को 2 महीने की गर्भवती बताया.

कांग्रेस विधायक के बेटे के खिलाफ शिकायत

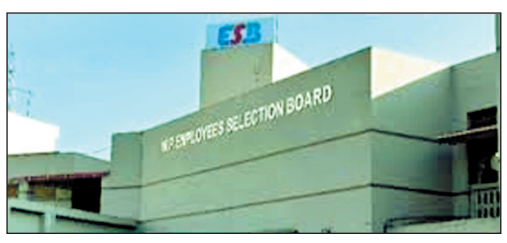
एमएलए रेस्ट हाउस में मारपीट का मामला

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 27 जून. एमएलए रेस्ट हाउस परिसर में कांग्रेस विधायक के बेटे और आरोपी की मां की तरफ से पुलिस में शिकायत का मामला सामने आया है. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से अरेरा हिल्स थाना पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़ा किया है.

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर के बेटे देवराज सिंह ने अपने साथ की गई मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज कराई. देवराज ने लक्की यादव को मामले में आरोपी बनाया है. मामला सामने आने के बाद लक्की यादव की मां ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर लक्की यादव की पिटाई देवराज की तरफ से किए जाने की शिकायत की है. लक्की की मां ने मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर जांच की मांग कमिश्नर से की है. बताया जा रहा है कि मामला 24 जून का है. देवराज सिंह ने परिसर के अंदर शराब पीने से मना करने पर कुछ युवकों द्वारा उनके साथ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई थी. अरेरा हिल्स थाना पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया.

इसी मामले में लक्की यादव की मां ने देवराज और उनके साथियों के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर बताया कि उनके बेटे की बुरी तरह से उस रात पिटाई की गई, जिससे उनके बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस ने एक ही पक्ष की शिकायत सुनीं.



फर्जी बोनस अंक लेकर मेरिट में आने वालों पर हाईकोर्ट का डंडा

8 जुलाई तक पोर्टल पर अपलोड करने होंगे वैध सर्टिफिकेट

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 27 जून. विशेष शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिना योग्यता के मेरिट सूची में जगह बनाने वाले फर्जी अभ्यर्थियों की अब खैर नहीं है. मप्र हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने अपनी बड़ी चूक को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है.

मंडल ने अपना आधिकारिक पोर्टल दोबारा खोल दिया है, जहां सभी चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त अपना दो वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा. साल 2025 में आयोजित हुई 3200 विशेष शिक्षकों के पदों की भर्ती परीक्षा हुई थी. जिसमें परीक्षा के बाद जब परिणाम आया तो क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 हजार पार कर गई, जो प्रदेश में मौजूद आरसीआई डिप्लोमा धारक वास्तविक युवाओं की कुल तादाद से भी कहीं ज्यादा थी. वहीं जांच में सामने आया कि आवेदन फॉर्म भरते समय केवल हां या ना का एक साधारण विकल्प रखा गया था. डिप्लोमा होने के दावे पर पांच प्रतिशत बोनस अंक मिलने थे. इसी का फायदा उठाकर सैकड़ों अयोग्य अभ्यर्थियों ने फॉर्म में हां का विकल्प चुन लिया और बोनस अंकों की बैसाखी के सहारे मेरिट लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए. फिलहाल अब उम्मीदवारों को 8 जुलाई तक का समय दिया गया है. जिसमें उन्हे वैध आरसीआई पंजीयन सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा न करने पर अभ्यर्थी सीधे चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिये जायेंगें.

